

प्रेषक,

निदेशक

कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला

देहरादून

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / वित्त नियंत्रक / कोषागार अधिकारी
उत्तराखण्ड।

दिनांक 04 अक्टूबर, 2010

विषय: दिनांक 09-11-2000 के पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 09-11-2000 के पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु विहित प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/पेंशनर्स संगठन/कोषागारों द्वारा मार्ग दर्शन मांगा गया है। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड द्वारा समय समय पर निर्गत निम्नलिखित शासनादेशों में विहित प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश -

- 1- शासनादेश संख्या-1135/पांच-6-2001-294/96, दिनांक 27 जून, 2001
- 2- शासनादेश संख्या-1209/पांच-6-2004-294/96, टी0सी0, दिनांक 09 अगस्त, 2004
- 3- शासनादेश संख्या-3531/5-6-04-294/96, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004

उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत शासनादेश -

- 1- शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04 सितम्बर, 2006
- 2- शासनादेश संख्या-503/XXVII(7)/2010, दिनांक 26 मई, 2010
- 3- शासनादेश संख्या-585/XXVii(7)/2010, दिनांक 08 जून, 2010
- 4- शासनादेश संख्या-546/XXVIII-3-2010-437/2002टी0सी0, दिनांक 03 अगस्त, 2010
- 5- शासनादेश संख्या-636/XXVIII-3-2010-437/2002(टी0सी0-I), दिनांक 20 अगस्त, 2010
- 6- शासनादेश संख्या-670/XXVII(7)/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010

कृपया इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(जी0 के0 पन्त)

निदेशक

प्रेषक,

श्री सुजीत बनर्जी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

550

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

दिनांक 27 जून, 2001

विषय—उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3975/पांच-6-97-294/96, दिनांक 01 जनवरी, 1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश द्वारा किये गये अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत रु० 10,000 से अधिक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, निदेशक, चिकित्सा है। इस प्रकार के दावों के बड़ी संख्या में प्राप्त होने के कारण निदेशक, चिकित्सा के स्तर पर परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षर करने की केन्द्रीकृत व्यवस्था से इनके त्वरित निस्तारण में अनुभव की आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों तथा चिकित्सा उपचार, पैथालाजिकल टेस्ट और दवाओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करके इसे सरल बनाने और शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2. अतएवं राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर तथा स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं—

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
(क) प्रदेश के अन्दर		
(1) रु० 2000 तक	राजकीय चिकित्सा का प्रभारी कार्यालयध्यक्ष। चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक जहाँ उपचार किया गया हो अथवा जहाँ से संदर्भित किया गया हो।	
(2) रु० 2000 से अधिक किन्तु रु० 10,000 तक।	उपचार करने वाले अथवा संदर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक।	विभागाध्यक्ष।
(3) रु० 10,000 से अधिक किन्तु रु० 50,000 तक।	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।)	शासन के प्रशासकीय विभाग।

(4) रु० 50,000 से अधिक

मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, शासन के प्रशासकीय विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं परामर्श एवं वित्त विभाग की है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा सहमति से।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।)

समस्त मामले

मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, शासन के प्रशासकीय विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं परामर्श एवं वित्त विभाग की है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, सहमति से।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

3. सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुए हों।

4. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल, वह मण्डल माना जायेगा, जहाँ से ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारों/अधिकारों की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वही माना जायेगा कि जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

5. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात् विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण करा कर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगे।

6. सेवारत कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तर-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी। यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-2 के बिन्दु (1) व (2) में उल्लिखित रु० 10,000 तक के दावे को किन्हीं कारणोंवश सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो उसे परीक्षण करे प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त उसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के प्रशासकीय विभाग को वापस किया जाय। ऐसे दावे किसी भी दशा में बिना परीक्षण के वापस नहीं किये जाने चाहिए।

7. गैर सरकारी चिकित्सालयों में उपचार :

(क) प्रदेश के भीतर के गैर सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय चिकित्सालयों में ऐसी चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसा प्रमाणित किये जाने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। किन्तु प्रदेश के बाहर ऐसी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) संदर्भित शासनादेश संख्या 3975/पाँच-6-97-294/96, दिनांक 01 जनवरी, 1998 इस सोपान तक संशोधित सम्पन्न जाय।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-जी(2) 1048/दस-2001, दिनांक 12-6-2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजोत बनर्जी, प्रमुख सचिव

प्रेषक,

श्री प्रीतम सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवाने,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उपप्र०,

लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक-09 अगस्त 2004

विषय- उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1135/5-0-2001-294/98, दिनांक-27.08.2001

के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सेवारत एवं सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश के बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे दावों के त्वरित निस्तारण में अनुमति की जा रही व्यवहारिक कठिनाइयों तथा चिकित्सा उपचार पैथालॉजिकल टेस्ट एवं दवाओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कार्यालयीय, विभागाध्यक्षों एवं शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतएव राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु शासनादेश दिनांक-27.08.2001 द्वारा की गयी व्यवस्था को संशोधित करते हुए निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं-

क0स0	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4
(क)	प्रदेश के अन्दर एवं बाहर		
1-	रु०-40,000.00 तक	राजकीय चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक जहाँ उपचार किया गया हो अथवा जहाँ से सन्दर्भित किया गया हो।	कार्यालयाध्यक्ष

2-	रु०-40,000.00 अधिक किन्तु रु०- 1,00,000.00 तक	उपचार करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले प्रशासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	विभागाध्यक्ष
3-	रु०-1,00,000.00 से अधिक किन्तु रु०- 2,00,000.00 तक	मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग
(ख)	प्रदेश के अन्दर एवं बाहर		
	रु०-2,00,000.00 से अधिक	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं, वहाँ संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

3- चिकित्सा अग्रिम

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिए चिह्नित/ सन्दर्भित चिकित्सालय/ संस्थान के प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी प्रशासक द्वारा दिये गये व्यय प्राक्कलन के आधार पर उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित स्वीकर्ता अधिकारी-कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष तथा शासन के प्रशासकीय विभाग जिस सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम है, उसके 75 प्रतिशत तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति करने के लिए भी अधिकृत होंगे। रुपया-2,00,000.00 से अधिक के चिकित्सा अग्रिम के मामले में प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी।

चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित बातों का अनुपालन आवश्यक होगा--

(क) अग्रिम स्वीकृति होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा निरन्तर उपचार चलते रहने की दशा में उपचार समाप्ति के तीन माह के अन्दर जो भी पहले हो, उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ऐसे अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों/

अर्ह अग्रियों के लिए रखा जायेगा जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से एकमुश्त कर ली जायेगी और एकमुश्त वसूली सम्भव न होने पर उसे मासिक किराओं पर वसूल किया जायेगा।

(ग) जब तक एक अग्रिम का समायोजन नहीं हो जाता है तब तक दूसरा अग्रिम किसी भी दशम में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(घ) अग्रिम के बिल पर आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में कर ली गयी है।

4- सेवा निवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा नृत्त सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालय/पक्ष जो अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से वह सेवा निवृत्त हुए हों।

5- इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा नृत्त सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल माना जायेगा, जहाँ से ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारी/ अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वहीं माना जायेगा जिस मण्डल से कर्मचारी/ अधिकारी सेवा निवृत्त हुआ हो।

6- उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात् विलम्बतः एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात् सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के कार्यालय/पक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगे।

- ४- चिकित्सा परिपूर्ति का स्वीकृत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण होना अनिवार्य होगी।

सामय / मिह द्वाचक्षर की युवा प्रतिष्ठिति संलग्न है।

- 2- शासक बिल/ बाधक चिकित्सक द्वारा प्रत्यागित है।
- 3- अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 4- अनिवार्यता प्रमाण में योग्यता, अनुभव, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है तथा जरा मिलान संलग्न है।
- 5- अनिवार्यता प्रमाण पत्र में सहस्रविदा उपचार अवधि को भीतर के तिथियों के ही बिल बाधक का ही भुगतान किया जाये।
- 6- अनिवार्यता प्रमाण पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतीहस्ताक्षरित है।
- 7- प्रदेश के भीतर विशिष्ट चिकित्सा संस्थान तथा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में उपचार कराने हेतु सेवास्त कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रकरण में प्राधिकृत चिकित्सक का सन्दर्भ तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रकरण में मण्डलीय चिकित्सा परिषद/ राज्य चिकित्सा परिषद का सन्दर्भ/ कर्मोत्तर संशुति संलग्न है।
- 8- प्रदेश के बाहर अन्य राज्य के चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने पर शासकीय अनुमति/ कर्मोत्तर अनुमति संलग्न है।

विचिन्तना करके प्रतिपूरित के पात्रों की स्वीकृति उसी दशा में प्रदान की जाय जब पूरा हेतु समस्त शर्तों/ औपचारिकताओं की पूर्ति हो. प्रथम तो, यदि किन्हीं मामलों में अध्यापक, अध्यापिका, कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी हो तो उन्हें पूर्ण जानकारी को अनिवार्य

॥ शास्त्र के अनुसार विद्य. लय ।

संयोजित संशोधन संख्या 1425/5-11-2003-2004/003, दिनांक-27.09.2003 एवं
 शासनादेश संख्या 2572/5-1-01, दिनांक-29.07.2001, एवं सोमनाथ संयोजित संशोधन
 संयोजित।

10- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

11- यह आदेश विदेश विभाग की अशासकीय संख्या-जी(2)1323/दरा-2001, दिनांक-17.07.
 2001 में प्राप्त समन्वय संशोधन से जारी किये जा रहे हैं।

संयोजित,
 10-02-
 श्री प्रवीण सिंह
 प्रमुख अधिकारी

निर्देश-1202(1)/111-9-2001-संयोजित

प्रतिनिधि निदेशिकाओं को सुपुनर्गठन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए।

- 1- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी/ सचिव, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 2- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 3- सार्वजनिक जिला अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 4- सार्वजनिक विभाग, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 5- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी एवं सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 6- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 7- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 8- निर्देशक (संयोजित संयोजित), सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 9- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।
- 10- सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक प्रमुख अधिकारी।

आदेश 11,
 11-02-
 श्री प्रवीण सिंह
 प्रमुख अधिकारी

सम्मिलित है। अतएव रु. 1.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संख्या-3381(1)/5-6-04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आज्ञा से, जय प्रकाश पाण्डेय, अनु सचिव।

चिकित्सा अनुभाग-6

3381/5-6-04/2003/01

लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 04

विषय : उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1942/5-6-2003-294/96 दिनांक 29.08.03 जिसके द्वारा उ.प्र. शासन की सेवा से सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों, जो स्थायी रूप से दिल्ली में निवास कर रहे हैं, एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ को अधिकृत किया गया था, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों, जो उत्तरांचल राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल बरेली एवं सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को अधिकृत किया जाता है।

2-उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य में निवास कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे उनके अधिभाषक द्वारा तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल बरेली अथवा सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को प्रेषित किये जायेंगे।

3-शासनादेश संख्या-1942/5-6-03-294/96, दिनांक 29.08.03 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4-यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

सिद्धार्थ बेहरा, प्रमुख सचिव।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

3381/5-6-04/2003/01

लखनऊ : दिनांक 4 अप्रैल, 2003

विषय: मकान, किराया भत्ते की अनुमन्यता के संबंध में।

शासनादेशसंख्या जी-1-1793/दम-81-2009/81, दिनांक 15-12-81 के प्रसार-4(2) में यह व्यवस्था है कि "यह भत्ता उन सरकारी सेवकों को नहीं दिया जायेगा जो सरकार द्वारा दिये गये निवास गृह में, जिनमें पुल् हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित भवन भी शामिल हैं, रहते हों या जिन्हें सरकार द्वारा निवास गृह दिया गया हो किन्तु जिन्होंने उसे लेने से इंकार कर दिया हो या जिन्हें सरकार आवास आवंटित किया गया हो, परन्तु दुरुपयोग के कारण आवास का आवंटन निरस्त कर दिया गया हो या जो आवंटित सरकारी आवास स्वयं छोड़कर अन्य सरकारी किराये के आवास में चले गये हों," उपर्युक्त व्यवस्था के कारण शासकीय आवास छोड़कर सी.एस.आई. ट्रॉजिन्ट हास्टल, गोमती नगर, लखनऊ में रह रहे अधिकारियों का आवास किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है जबकि यह अधिकारी सी.एस.आई., लखनऊ द्वारा निर्धारित किराये का भुगतान कर रहे हैं।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर सी.एस.आई. ट्रॉजिन्ट हास्टल की विभागीय प्रास्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक सरकारी आवास को छोड़कर सी.एस.आई. ट्रॉजिन्ट हास्टल, गोमती नगर, लखनऊ में रहता है और वह प्रचलित आवासों का किराया अपने वार्षिक वेतन के 10 प्रतिशत तक देता है तो प्रकाश किराया भत्ता अनुमन्य नहीं होगा किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक किराया देने की दशा में सरकारी सेवक की वेतन के 10 प्रतिशत तक किराया स्वयं वहन करना होगा और उसके ऊपर निर्धारित सीमा तक निर्धारित शर्तों के अधीन मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

आनन्द मिश्र, सचिव।

"551"

प्रपक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 04 सितम्बर 2006

विषय :- उत्तरांचल के सरकारी सेवाओं की चिकित्सा परिचर्या के संबंध में
दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-180/चि-2-2003-437/2002 दिनांक 20.12.2003 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल के संघराज एवं सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश के बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुये व्यय की पूर्ति के संबंध में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे दावों के त्वरित निस्तारण में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाईयों तथा चिकित्सा उपचार, पैथालॉजिकल टेस्ट एवं दवाओं के मूल्य में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्बन्ध विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कार्यालयध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतएव श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 20.12.2003 द्वारा की गयी व्यवस्था को संशोधित करते हुये निम्नंकित निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------

1) रु0 40,000.00 तक

राजकीय चिकित्सालय के
अधीक्षक/मुख्य अधीक्षक जहाँ
उपचार अथवा जहाँ से सन्दर्भित
किया गया हो। अशासकीय
चिकित्सालयों के प्रकरण में
राजकीय चिकित्सालय के लक्ष्य
प्राधिकारी।

कार्यालयध्यक्ष

2)रू0 40,000.00 से अधिक किन्तु रू0 1,00,000.00 तक	उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।	विभागाध्यक्ष
3)रू0 1,00,000.00 से अधिक किन्तु रू0 2,00,000.00 तक	कुमार्यू मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमार्यू मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	शासन के प्रशासकीय विभाग
	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी एवं उनके परिवार के आश्रितों तथा उत्तरांचल सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों हेतु निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तरांचल।	
4) रू0 2,00,000.00 से अधिक	-----तदैव-----	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

3-चिकित्सा अग्रिम:-

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिये चिन्हित/सन्दर्भित चिकित्सालय/संस्थान के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी प्रशासक द्वारा दिये गये व्यय प्राक्कलन के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा रू0 2,00,000/-तक की सीमा तक के व्यय प्राक्कलन पर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। रू0 2,00,000/-से अधिक के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा उपचार अग्रिम हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पाँच भाग-एक के प्रस्तर-249 में निर्धारित सीमा रू0 25,000/-को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

उपरोक्त अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा:-

- ऐसे अग्रिम की धनराशि अनुमानित व्यय आगमन के 75 प्रतिशत से अधिक न हो।
- अग्रिम स्वीकृत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा निरन्तर उपचार चलते रहने की दशा में उपचार समाप्ति के तीन माह के अन्दर, जो भी पहले हो उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ग) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु अधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों के लिये परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र पर रखा जायेगा जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा की जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से एक मुश्त कर ली जायेगी और एक मुश्त वसूली सम्भव न होने के कारणों के विस्तृत परीक्षण के बाद औचित्यपूर्ण स्थिति में मासिक किशतों में न्यूनतम सम्भव वसूल किया जायेगा।
- (घ) जब तक एक अग्रिम का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक दूसरा अग्रिम किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (ङ.) अग्रिम के विल पर आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में कर ली गई है।
- (च) फालोअप ट्रीटमेन्ट के लिये अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

4- चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यता:-

(i) प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचार :-

- (क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य बीमारी अथवा सामान्य दवा के कैश मेमो पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार की जाय।
- (ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐसी उपचार प्रणालियों/परीक्षणों जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर की जायेगी।
- (ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम में कराई गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उन दरों पर की जायेगी जिन दरों पर इस प्रकार की चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में कराने पर व्यय आता है। प्रतिपूर्ति की धनराशि वास्तविक दावे अथवा सरकारी चिकित्सालय में उक्त उपचार हेतु व्यय की धनराशि/दरों में से जो भी कम हो, देय होगी किन्तु ऐसी उपचार प्रणालियां/परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध न हो, पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (घ) रूटीन बीमारियों का सरकारी चिकित्सालयों से इतर उपचार कराने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक का संदर्भण आवश्यक होगा।

(ii) प्रदेश के बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा :-

असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचारार्थ प्रदेश स्थित चिकित्सालयों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृत आदेश प्राप्त करेंगे।

(iii) प्राधिकृत चिकित्सक के सन्दर्भ पर उन उपचार प्रणालियों/परीक्षणों, जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में न उपलब्ध हो प्रदेश स्थित गैर सरकारी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार परीक्षण की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर तभी अनुमन्य होगी जब प्रतिहस्ताक्षरार्थ अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि राजकीय चिकित्सालयों में उक्त उपचार प्रणालियाँ/परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(iv) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे जहां से वह सेवानिवृत्त हुये हों। 30प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रस्तर-54 के साथ पठित शिड्यूल-8 के अनुसार उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स जिस कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हों, द्वारा यह प्रमाणित करने पर उक्त पेंशनर किस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तथा संबंधित कार्यालय उत्तरांचल के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं था तथा उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान पेंशन के सुसंगत लेखा शीर्षक से करने के बाद दोनों राज्यों के मध्य धनराशि जनसंख्या के आधार पर प्रभाजित की जायेगी।

(v) ऐसे सरकारी सेवानिवृत्त सेवक जो पुर्ननियुक्ति पर कार्यरत हैं कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले उनके मूल पैतृक विभाग के माध्यम से तथा जिस प्रदेश से उनकी पेंशन आहरित की जा रही होगी, उसी प्रदेश से नियमानुसार व्यवहरित किये जायेंगे।

(vi) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवकों के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल माना जायेगा, जहां से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वही माना जायेगा कि जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

7- उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा ।

चेक लिस्ट

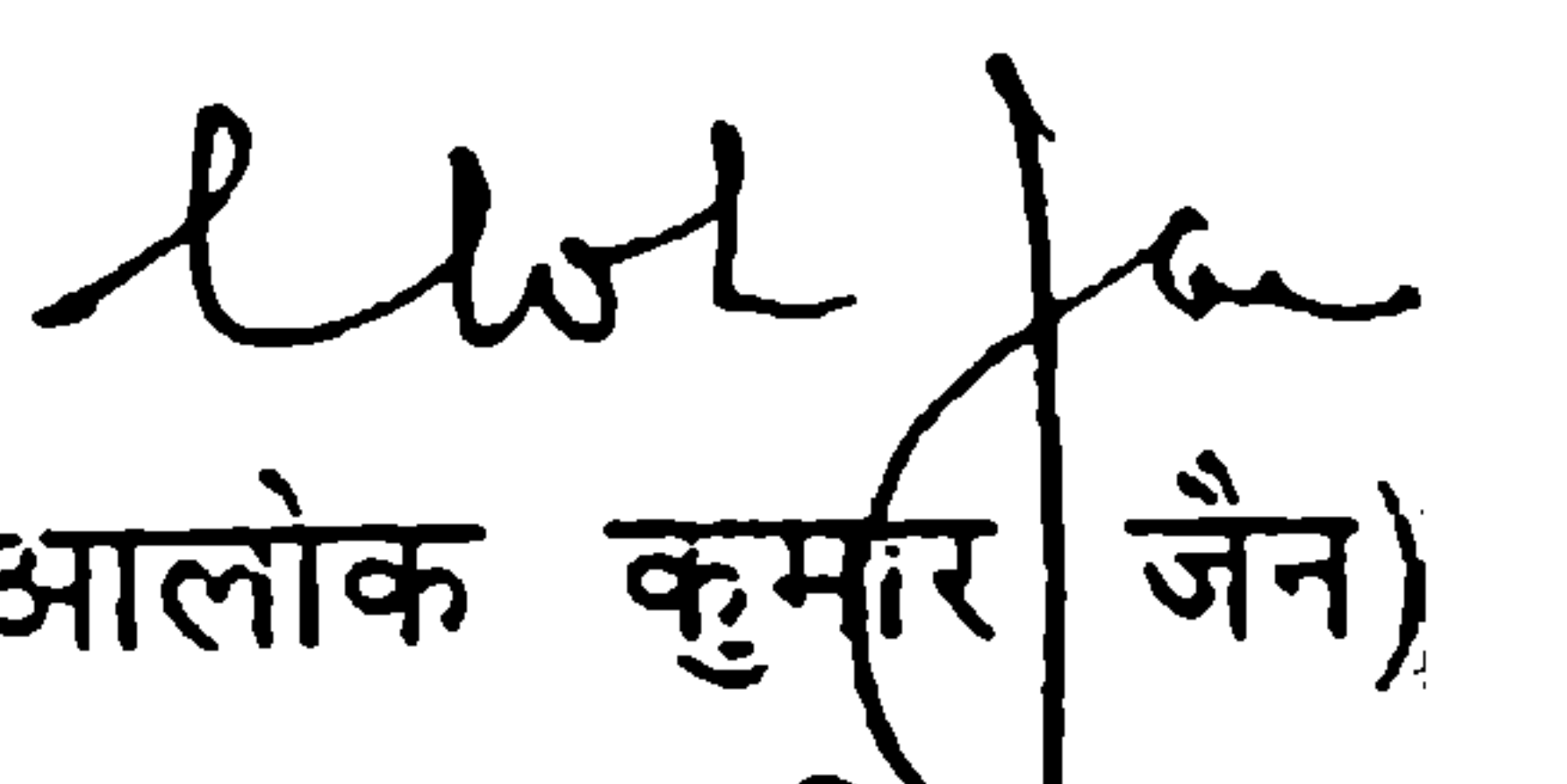
- समस्त/बिल वाउचर की मूल प्रतिलिपि संलग्न हो।
- समस्त बिल/वाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल वाउचर का भुगतान किया जायेगा।

- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्साल के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
- प्रदेश में बाहर के चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराये जाने की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी होगी।

8- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा शासन संख्या-1180/चि0-2-2003-437/2002, दिनांक 20.12.2003, इस सीमा तक संशोधित स जायें।

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-432/वित्त-3/2006, दि 18.08.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथांपरि।


भवदीय,

 (आलोक कुमार जैन)
 प्रमुख सचिव।

संख्या: 679 (1)/चि-3-2006-437/2002 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, जिला पुरुष एवं महिला चिकित्साल उत्तरांचल।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. एन0आई0सी0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


 (अनुर सिंह)
 उप सचिव

अनिवार्यता प्रमाण पत्र

बाह्य रोगी/अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

..... प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... पुत्र/पुत्री/माता/पिता विभाग जो रोग से पीड़ित हैं/थे व मेरे उपचार में
बाह्य रोगी के रूप में तथा/अथवा अन्तः रोगी के रूप में दिनांक से तक रहें।

2. मेरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न बाउचर के अनुसार हैं, रोगी की स्थिति में सुधार/निवारण के लिये आवश्यक थी। इसमें ऐसी औषधि सम्मिलित नहीं है, जिसके लिये सामान थैरोप्यूटिक एफ़ेक्ट वाला सस्ता पदार्थ उपलब्ध है न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित है जो प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ, टायलेटरीज व डिसइन्फेक्टेंट हैं।

3. उपचार पर व्यय का विवरण :

(क)	औषधि पर व्यय	रु0
(ख)	पैथोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रु0
(ग)	रेडियोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रु0
(घ)	विशेष परीक्षण पर व्यय	रु0
(च)	शल्य क्रिया पर व्यय	रु0
(छ)	अन्य व्यय (विवरण सहित)	रु0

योग रु0

रोगी को चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किये जाने की आवश्यकता थी/नहीं थी।

संलग्नक :- मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित/अभिप्रमाणित बिल/बाउचर संख्या

हस्ताक्षर

चिकित्सक या शल्यक चिकित्सक

नाम योग्यता सहित सील

आकस्मिक स्थिति में बिना मंदर्मण के अराजकीय चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की दशा में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो रोग से पीड़ित
/थी एवं उन्हें आकस्मिक स्थिति में तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी व मेरे उपचाराधीन हैं/रहे।

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक

चिकित्सक या शल्य चिकित्सक
नाम योग्यता सहित सील

प्रमाणपत्र
प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ने चिकित्सालय में उपचार किया तथा दी गई
चिकित्सा सुविधा आवश्यक उपचार हेतु न्यूनता थी तथा परीक्षण चिकित्सा परिचर्या नियमावली/संगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार किया
है तथा प्रतिपूर्ति हेतु जो दरें प्रमाणित की गयी हैं, वे नियमानुसार वास्तविक दरें हैं।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी

परिशिष्ट "क"

देश के अंदर चिकित्सा परिचर्या हेतु स्वीकृत अग्रिमों का रजिस्टर

कार्यालय का नाम													
क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पद	अग्रिम स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत अग्रिम को धनराशि	अग्रिम को तिथि एवं वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने की तिथि	प्रतिपूर्ति के दावा कार्यालय अधक्ष से प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	प्रतिपूर्ति के दावे भुगतान/अग्रिम की वसूली हेतु कृत कार्यवाही का विवरण	प्रचार काय की प्रतिपूर्ति की रवीकृति आदेश को संज्ञा एवं तिथि	प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि	समायो हेतु अग्रिम की अवशेष धनराशि यदि कोई हो	अग्रिम की अवशेष धनराशि यदि कोई हो जमा करने संबंधी ट्रेजरी चालान की संख्या एवं तिथि तथा जमा की गयी धनराशि	समायोजन धिल की संख्या एवं तिथि	आहरण -वितरण अधिकारी द्वारा जांच के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

रजि

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,
देहरादून।

वित्त (वे0आ0-सा0नि) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 26 मई, 2010

विषय:-अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (9-11-2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9-11-2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्यीय समायोजन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाये।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,

कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,

देहरादून।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-०७

देहरादून:दिनांक: ०८ जून, 2010

विषय:—अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 28, मई 2010 के तृतीय पंक्ति में प्राधिकार पत्र दिनांक 09-01-2010 के स्थान पर दिनांक 08-11-2000, पढ़ा जाए।

2— शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 28, मई 2010 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

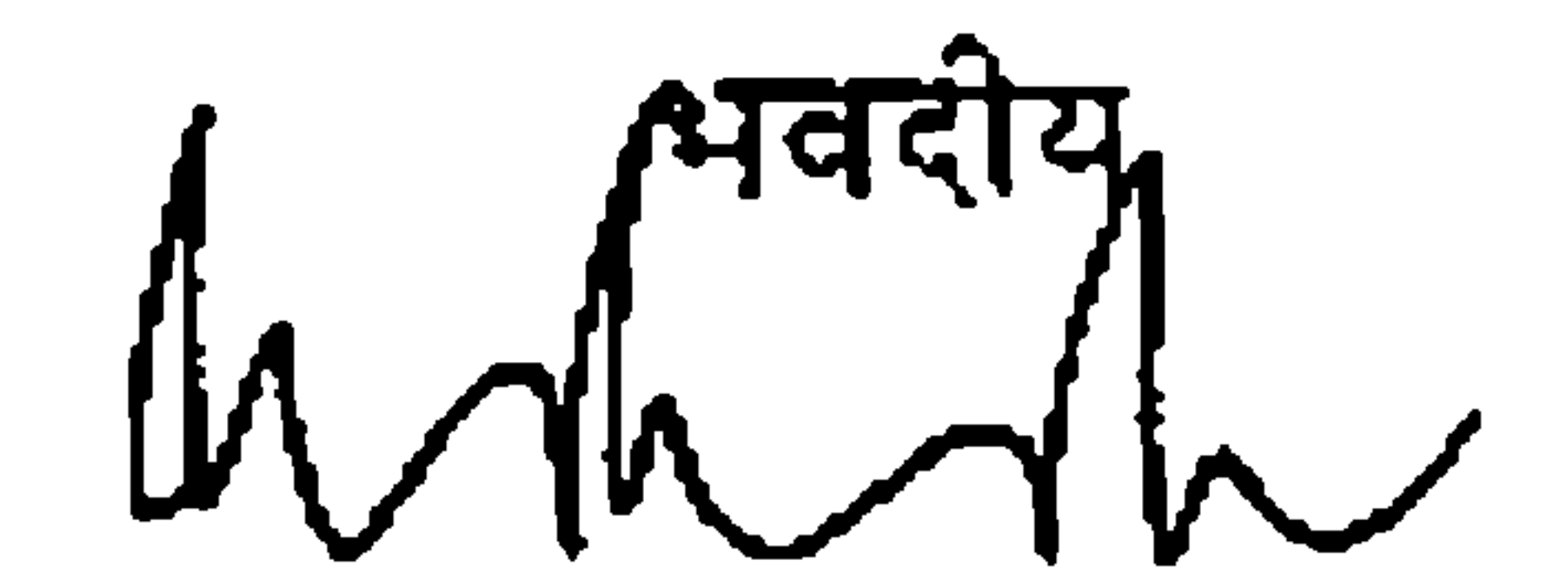
देहरादून: दिनांक 03 अगस्त, 2006

विषय: उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-4(ii) में निहित व्यवस्थानुसार विभिन्न प्रशासकीय विभागों में परामर्श हेतु संदर्भित प्रकरणों के परीक्षण आदि में प्रायः यह दृष्टिगत हो रहा है कि आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण बिना पूर्वानुमति के कराये गये उपचार के मामलों में उपचार भुक्त होने के 30 दिन के अन्दर उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा इस पर छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-4(ii) में आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा को 30 दिन के स्थान पर 60 दिन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश दिनांक 04.09.2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।



(डा० उमाकान्त पंवार)
सचिव।

प्र0संख्या- (1)/XXVIII-3-2010-437/2002टी0सी0, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधोक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंचर
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2010

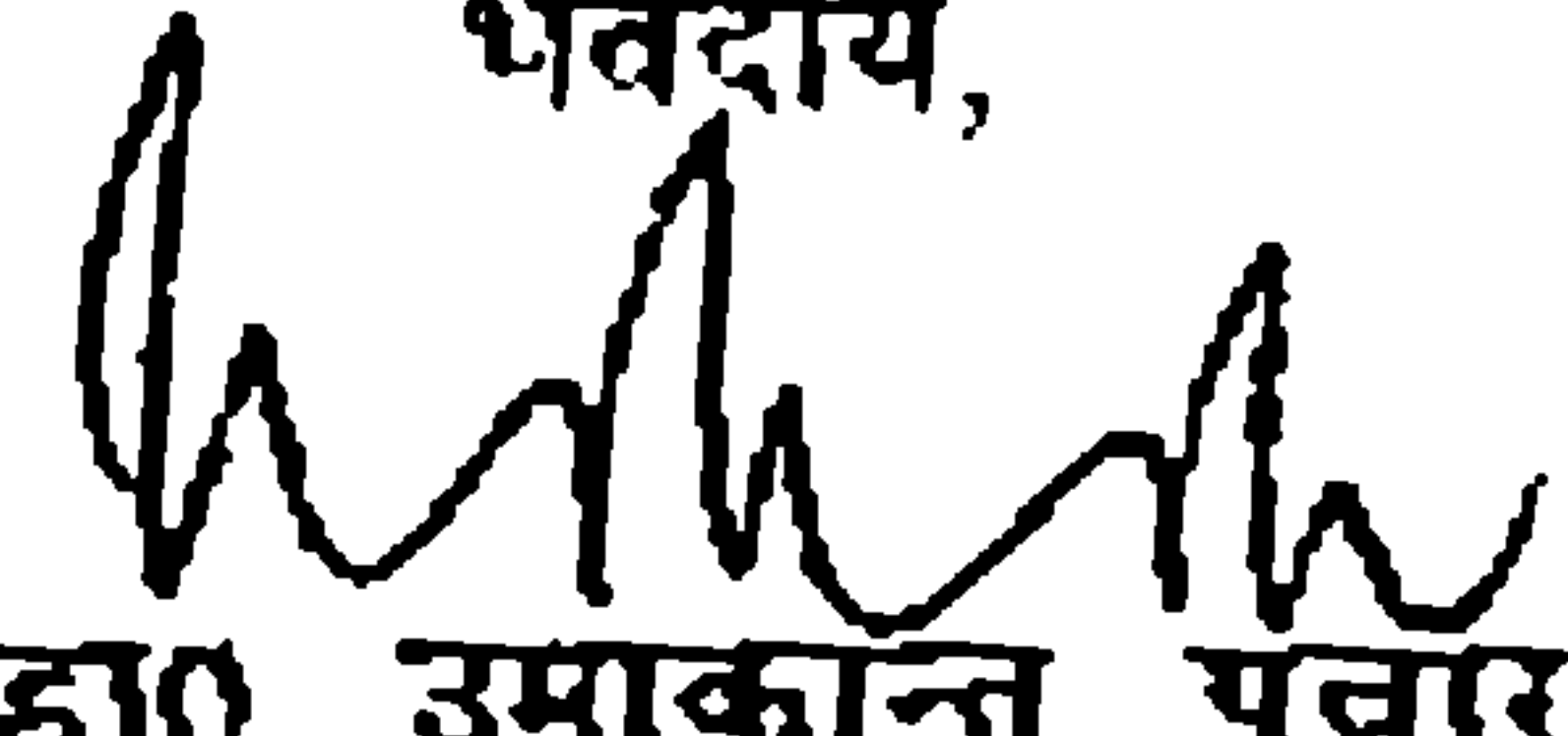
विषय: उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जो प्रदेश के बाहर निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के तकनीकी परीक्षण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-362/XXVII(8)/2005, दिनांक 19.09.2005, संख्या-58/XXVII(7)पे0/2006, दिनांक 18.05.2006 एवं चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त राज्य के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य, जो स्थायी रूप से दिल्ली, मेरठ मण्डल तथा सहारनपुर मण्डल में निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के पूर्व अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा दावों के मूल देयक के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को तथा उत्तराखण्ड राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो मेरठ मण्डल तथा सहारनपुर मण्डल के अतिरिक्त 30प्र0 राज्य के अन्य मण्डलों में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा दावों के मूल देयक के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, गौड़ी को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 08.05.2006 तथा 04.09.2006 के संगत अंश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय और इनकी शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-4399/XXVII(7)/2010, दिनांक 03.08.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० उमाकान्त पंचर)
सचिव।

पू०संख्या- (1)/XXVIII-3-2010-437/2002(टी०सी०-I), तददिनांक।

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. वित्त वे०आ०सा०नि० अनुभाग-7।
11. गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (बि०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7

संख्या 670/XXVII(7)/2010
देहरादून: दिनांक 24 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक: 9-11-2000 के पूर्व के पेंशनर्स को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा-54 की आठवीं अनुसूची के अनुसार पूर्व की भांति उत्तराखण्ड के शासनादेशों के अनुसार पेंशन व अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्रदान किया जाना।

उपर्युक्त विषयक सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक: 10-9-2010 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को उनसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (9-11-2000 के पूर्व), जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9-11-2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं, की प्रास्थिति अन्य राज्यों के पेंशनर्स के समान हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार दिनांक: 9-11-2000 के पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है कि अब वे उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनर्स हैं। उनका पेंशन पट्टा (पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर) उत्तर प्रदेश राज्य ने ही दिया है। अतः उत्तराखण्ड के आदेश उन पर लागू किया जाना विधि के अनुरूप नहीं है।

2-स्पष्टतः दिनांक 9-11-2000 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स तथा वे पेंशनर जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9-11-2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं उनकी समस्त देयता उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। अतः इनके पेंशन/पेंशन राहत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के आधार पर महालेखाकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना विधिसम्मत है।

3-महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त श्रेणी के पेंशनर्स के पेंशन, पेंशन राहत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि लाभों के भुगतानों को मुख्य लेखा

शीर्षक-2071 के बजाय लेखा शीर्षक-8793-अन्तर-राज्य उच्चन्त लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय जैसा कि अन्य राज्य के पेंशनर्स के भुगतानों हेतु किया जाता है, ताकि उक्त भुगतानित धनराशि का सही लेखांकन एवं कोषागारों द्वारा भुगतानित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

4-इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी शासनादेश दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो उत्तराखण्ड में स्थायी निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा परिवार के उन पर पूर्णतः आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हुए इन दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनर्स जो उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु इसी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा सुनिश्चित की गयी है।

उक्त समग्र तथ्यों के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 26-5-2010 को निरस्त किये जाने/संशोधित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(राधा शर्मा)
सचिव वित्त।

श्री आर०एस० परिहार,
प्रदेश अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड,
कैम्प कार्यालय 6 प्रीति विहार, इंदिरा गाँधी मार्ग, निरंजनपुर,
पोस्ट, माजरा, जनपद देहरादून।

A circular library stamp from the University of Madras. The text "UNIVERSITY OF MADRAS" is curved along the top inner edge, and "LIBRARY" is curved along the bottom inner edge. In the center, the year "1981" is printed above the date "11/12". At the bottom, the text "CHENNAI" is visible.

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयधर्मा
उत्तराखण्ड शासन :

1771(1950-51) 40000000-07

महोदय,


3- राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तराज्जीय समायोजन के माध्यम से किया जाएगा।

भवदीय.
(हमलता ढोंडियाल)
राधिय वित्त ।

संख्या २८९८ (I)/XXVII (7) 09(II)/ 2011, तदनुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- सचिव, राज्य योजना / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख मन्त्रि, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 9- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमाऊं।
- 11- रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिशनर, कानपुर/देहरादून।
- 12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की।
- 15- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0अई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
- 16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(श्री चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त